सुरक्षा, शांति और समृद्धि

सजग भारत

01-15, जुलाई, 2023 वर्ष-1 अंक-7

निःशुल्क प्रति

डिजिटल युग में मजबूत होती

भारत की साइबर सुरक्षा

जी20 सम्मेलनः NFTs, AI और Metaverse के दौर में अपराध और सुरक्षा पर चिंतन

वसुधैव कुटुम्बकम्

ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

अनुक्रमणिका

साइबर सुरक्षित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार	11
साइबर सुरक्षा : भारत के विकास में है अहम भूमिका	14
चंद्रयान-3 से देश की आशाओं को लगेंगे पंख	18
भारत को जोड़ती है गीता प्रेस	20
आपदा प्रतिरोधी तंत्र विकसित करना हमारी प्राथमिकता	21
हवाई अड्डों को मिला और अधिक सुरक्षा कवच	23
संवाद, सोच और सफलता	24
प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण और साइबर सुरक्षा ...	26

विशेष रिपोर्ट

05 डिजिटल युग में मजबूत होती भारत की साइबर सुरक्षा

19 सम्मान और साझेदारी की उड़ान

25 परियोजनाओं की समीक्षा से मिले सकारात्मक...

संपादक की कलम से

बालाजी श्रीवास्तव
महानिदेशक, बीपीआरएंडडी

प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा-वैश्विक सुरक्षा का मामला बन गया है।

इंटरनेट की उपयोगिता आज सर्वसिद्ध है। गांव हो या कस्बा, शहर हो या महानगर, जब सामान्य जीवन पर प्रतिबंध लगा, तो इंटरनेट ने समाज और देश को अपनी जरूरतों को पूरा करने का आधार दिया। हम अपने साइबर व्यावसायिकों के प्रति कृतज्ञ हैं, जिनके कारण यह संभव हो पाया।

विज्ञान एक ओर सहूलियत प्रदान करता है, तो दूसरी ओर इसके माध्यम से समस्याएं भी आ सकती हैं। इंटरनेट की दुनिया में भी ऐसा ही हो रहा है, जिसे हम 'साइबर अपराध' के नाम से जानते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई के साथ इंटरनेट के बुनियादी ज्ञान ने नई छलांग लगाई है, जिससे उन कार्यों को भी सम्पन्न किया जा रहा है, जो कभी पूरी तरह से मनुष्यों के अधिकार क्षेत्र में थे। इसी तरह की छलांग मेटावर्स में भी देखी जा सकती है। इसके अलावा, यह परिवर्तन क्रिप्टो मुद्रा मॉडल और अपूरणीय टोकन (एनएफटी) की शुरुआत के माध्यम से वित्तीय दुनिया तक फैल गया है। अपराधियों ने भी अपने नापाक उद्देश्यों के लिए साइबर स्पेस का भरपूर लाभ उठाया है। अपराधी तेजी से डार्क नेट का उपयोग कर रहे हैं, जिससे वर्तमान में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए नित नई चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं।

प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा-वैश्विक सुरक्षा का मामला बन गया है। साइबर अपराध की उभरती प्रवृति और इसके संभावित परिणामों को पहचान कर भारत की जी20 की अध्यक्षता के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 'एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा' विषय पर दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया और साइबर अपराध के वैश्विक अंतरसंबंध को पूरी दुनिया के सामने विस्तार से रखा। उन्होंने विश्व समुदाय से इस खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सीमाओं के पार गठबंधन बनाने का आग्रह किया। वर्चुअल एसेट्स माध्यमों के उपयोग पर नकेल कसने के लिए एक मजबूत और कारगर ऑपरेशनल सिस्टम की दिशा में, हमें एकरूपता से सोचना होगा।

दुनिया के कई देश भारत की चिंता के साथ काम करने और साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक साथ आने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सम्मेलन में केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय मिश्रा जी, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर जी, केंद्रीय गृह सचिव, श्री अजय कुमार भल्ला जी की सक्रिय भागीदारी से सरकार की प्रतिबद्धता को बल मिला। समापन सत्र के दौरान अपने वक्तव्य में केंद्रीय मंत्री, श्री अश्विनी वैष्णव जी ने बेहद मूल्यवान अंर्तदृष्टि प्रदान की।

हम 'सजग भारत' के 7वें अंक में साइबर सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से बात कर रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया और सुझावों की प्रतीक्षा है। आप अपनी बात हम तक dg@bprd.nic.in के माध्यम से भेज सकते हैं।

जय हिंद!

वसुधैव कुटुम्बकम, यानि पूरा विश्व एक परिवार है। यह सिद्धांत, प्राचीन समय से हमारे सामाजिक आचरण का अभिन्न अंग रहा है। और आधुनिक समय में भी हमारे लिए एक नयी प्रेरणा और ऊर्जा का स्रोत है।

-श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा-वैश्विक सुरक्षा का मामला बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के ह्यूमेन आस्पेक्ट पर जोर दिया है। टेक्नोलॉजी के उपयोग में 'कम्पैशन' और 'सेंसिटिविटी' सुनिश्चित करने के लिए 'इन्टरनेट ऑफ थिंग्स' को 'इमोशन्स ऑफ थिंग्स' के साथ जोड़ा है।

-श्री अमित शाह
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

जल जीवन मिशन के तहत 11 करोड़ से अधिक घरों में नल कनेक्शन, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना से 22 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के स्वास्थ्य की चिंता की गई, ई-नाम प्लेटफार्म पर 1.74 करोड़ किसानों का पंजीकरण और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत **23.2** लाख करोड़ का लोन दिया जा चुका है।

- श्री नित्यानंद राय
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

The launch of PM MITRA Park in Maharashtra epitomizes the power of Hon'ble PM Sh @ narendramodi ji's 5F vision. #PragatiKaPMMitra amplifies the momentum, ushering in a remarkable era of growth, innovation, and endless possibilities.

-Shri Nisith Pramanik
Union Minister of State for Home Affairs

LVM3 M4 vehicle successfully launched Chandrayaan-3 into orbit. Congratulations to all the scientists who worked for this project. @isro

-Shri Ajay Mishra
Union Minister of State for Home Affairs

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने अपराध और सुरक्षा पर हो रहे जी20 सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि कोई भी देश या संगठन, अकेले साइबर खतरों का मुकाबला नहीं कर सकता, हमें कन्वेंशनल जियोग्राफिक बॉर्डर से ऊपर उठकर सोचना होगा और इसके लिए एक यूनाइटेड फ्रंट की आवश्यकता है.

-गृह मंत्रालय, भारत सरकार

डिजिटल युग में मजबूत होती भारत की साइबर सुरक्षा

जी20 सम्मेलनः NFTs, AI और Metaverse के दौर में अपराध और सुरक्षा पर चिंतन

ब्यूरो

दुनिया बदल रही है। तकनीक ने हर चीज को बदल दिया है। ऐसे में चुनौतियां भी पहले से अधिक कठिन हो गई हैं। आतंक की दुनिया अब पारंपरिक रास्तों को छोड़कर तकनीक से लैस हो रही है। सुरक्षा चुनौतियां डायनामाइट से मेटावर्स और हवाला से क्रिप्टो करेंसी के दौर में पहुंच चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस सहूलियत के साथ सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां पैदा कर रहा है। जब पूरी दुनिया इन चुनौतियों से जूझ रही है, तो भारत ने एक नया विमर्श शुरू किया। जी20 के मंच से पहली बार एक साथ अपूरणीय टोकन (एनएफटी), कृत्रिम होशियारी (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा के विषय पर विशेषज्ञों ने बात की।

दुनिया भर में कई प्रतिभाशाली दिमाग साइबर स्पेस की विशाल क्षमता का उपयोग करके निरंतर नवाचारों और आविष्कारों के माध्यम से हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकियों में प्रगति हमारे

आज दुनिया नए world order की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। भारत इस समय जी20 का प्रेसीडेंट है। पहली बार किसी देश की प्रेसीडेंसी में ऐसा हो रहा है जब उस देश के कोने-कोने में 200 से ज्यादा बैठकें हो रही हैं। पूरा जी20 समूह भारत के सामर्थ्य को देख रहा है, उससे मंत्रमुग्ध है। क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल सप्लाई चेन हो, आतंकवाद हो, कट्टरवाद हो-हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव, भारत का प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है।

श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

कोई भी देश या संगठन, अकेले साइबर खतरों का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसके लिए एक संयुक्त मोर्चे की आवश्यकता है।

दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाई है। हमारे साइबर पेशेवरों की इन निरंतर उपलब्धियों ने मानवता के लिए सकारात्मक परिवर्तनों की शुरूआत की है। इसी प्रक्रिया में कब आतंकी संगठनों की सेंध लगी, पता नहीं चला। जो आविष्कार लोगों की सुविधा के लिए बने, उसको हैक करके परेशानी में बदलने की कोशिश हो रही है। यह केवल एक देश की नहीं, दुनिया के लगभग हर देश की कहानी बन चुकी है। सभी की समस्याओं को एक साथ एक मंच पर भारत ने लाने की पहल की है। जी20 के मंच पर दुनिया के दिग्गजों ने इसको लेकर अपने विचार रखे और एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया।

अपराध के इस नए युग के जवाब में, सुरक्षा के एक नए युग, साइबर सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता उत्पन्न होती है। दुनिया

साइबर अपराध और सुरक्षा पर सम्मेलन

एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर जी20 सम्मेलन में साइबर दुनिया में सबसे प्रासंगिक विषयों पर ध्यान केंद्रित करने वाले छह विषयगत सत्र शामिल थे। इन सत्रों में निम्नलिखित विषय थे :-

(ए) इंटरनेट गवर्नेंस - राष्ट्रीय जिम्मेदारी और वैश्विक कॉमन्स

(बी) डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) को सुरक्षित करना-डिजिटलीकरण की चुनौतियों को संबोधित करना, डिजाइन, वास्तुकला, नीतियां और तैयारी

(सी) विस्तारित वास्तविकता, मेटावर्स और डिजिटल स्वामित्व का भविष्य-कानूनी और नियामक ढांचा

(डी) आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-चुनौतियां, अवसर और जिम्मेदार उपयोग

(ई) डार्क नेट को समझना: क्रिप्टो करेंसी और डार्क नेट कनेक्शन की चुनौतियां (एफ) सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) के आपराधिक उपयोग को संबोधित करना-एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ढांचे का विकास करना

जब अधिकतर काम डिजिटल हो रहा है, तो नए समय का युद्ध भी अब डिजिटल तरीके से ही लड़ा जाएगा। डिजिटल युद्ध में टारगेट हमारे भौतिक संसाधन नहीं होते हैं, बल्कि हमारी ऑनलाइन कार्य करने की क्षमता को टारगेट किया जाता है। सुरक्षा की तैयारी नहीं रही तो कुछ ही मिनटों में ऑनलाइन नेटवर्क में व्यवधान घातक हो सकता है। एनएफटी, एआई और मेटावर्स को लेकर भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय की अगुवाई में जी20 के मंच पर दो दिनों तक विचार-विमर्श किया गया।

सम्मेलन की मुख्य बातें

- केन्द्रीय गृह मंत्री ने तेजी से जुड़ रही दुनिया में साइबर रेजिलिएन्स स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया
- साइबर क्राइम और डार्क नेट से रहना होगा सतर्क।
- प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों पर साइबर क्राइम का खतरा मंडरा रहा है।
- साइबर हमलों से सुरक्षा किसी एक देश के बूते की बात नहीं है और इसके लिए पूरी दुनिया को साझा प्रयास करना होगा।
- भारत के 'ओपन-एक्सेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' मॉडल आज विश्व में मिसाल बन रहे हैं।
- नागरिकों को डिजिटल प्लेटफार्मों पर हो विश्वास।
- इंटरनेट के जरिए फेक न्यूज भी काफी फैलाई जा रही है जो राष्ट्रीय चिंता का विषय है।
- डिजिटल स्पेस में असुरक्षित होना, नेशन-स्टेट की लेजिटिमेसी और संप्रभुता पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है।
- प्रभावी प्रिडिक्टिव 'प्रिवेंटिव' प्रोटेक्टिव एंड रिकवरी एक्शन हेतु एक 24x7 साइबर सिक्यूरिटी मैकेनिज्म होना चाहिए।
- जी 20 के मंच पर साइबर सुरक्षा पर सम्मेलन से, 'इनफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर' और 'डिजिटल पब्लिक प्लेटफार्मों' की सुरक्षा और संपूर्णता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

वर्तमान में एक साइबर-सुरक्षित और साइबर सफल समाज बनाने पर केंद्रित है। नतीजतन, इस नए साइबर युग में अपराध और सुरक्षा के मुद्दे नए हैं और उनके सामने आने वाली चुनौतियां कई गुना हैं। जी20 के इतिहास में साइबर सुरक्षा पर पहला सम्मेलन मील का पत्थर साबित होगा। यह आयोजन प्रौद्योगिकी के उभरते परिदृश्य और अपराध एवं सुरक्षा पर इसके प्रभाव से उत्पन्न उभरते खतरों और चुनौतियों को संबोधित करने पर केंद्रित था। चूंकि, भारत इस वर्ष जी20 का अध्यक्ष है, साइबर सुरक्षा पर यह ध्यान वैश्विक विकास में बाधा डालने वाले, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने के भारत के प्रयासों के अनुरूप केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, अमित शाह ने डिजिटल दुनिया की वास्तविकता पर प्रकाश डाला और इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ा, जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती है। सभी के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी की सुरक्षित और समावेशी पहुंच की वकालत करती है।

यह स्वीकार करते हुए कि प्रौद्योगिकी, भूगोल, राजनीति और अर्थव्यवस्था की पारंपरिक सीमाओं से परे है, केंद्रीय गृह मंत्री ने दुनिया को एक विशाल 'डिजिटल गांव' के रूप में बताया, जो व्यक्तियों को आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करने वाले असामाजिक तत्वों और वैश्विक ताकतों के खतरों का सामना करता है। सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि साइबर सुरक्षा पर वैश्विक सहयोग को तत्काल मुद्दों पर सहयोगात्मक प्रयासों के समान ही अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की अध्यक्षता में हो रही जी20 की बैठक में पहली बार साइबर सूरक्षा के लिए नई और अनूठी पहल हुई है। पिछले 10 वर्षों में भारत को एक डिजिटल राष्ट्र के रूप में परिवर्तन को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया कि किस तरह से भारत ने साइबर सुरक्षा के लिए कई अहम कदम उठाये हैं। लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि साइबर हमलों से सुरक्षा किसी एक देश के बूते की बात नहीं है और इसके लिए पूरी दुनिया को साझा प्रयास करना होगा। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि साइबर सुरक्षा अब केवल डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है। यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा-वैश्विक सुरक्षा का मामला बन गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने टेक्नोलॉजी के मानवीय पहलू पर जोर दिया है। टेक्नोलॉजी के उपयोग में 'कम्पैशन' और 'सेंसिटिविटी' सुनिश्चित करने के लिए 'इन्टरनेट ऑफ थिंग्स' को 'इमोशन्स ऑफ

हमारा इंटरनेट विजन न तो राष्ट्र के अस्तित्व को संकट में डालने वाला अत्यधिक फ्रीडम का होना चाहिए और न ही डिजिटल फायरवॉल जैसे आइसोलेशनिस्ट स्ट्रक्चर का होना चाहिए। भारत ने कुछ ऐसे 'ओपन-एक्सेस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर' मॉडल खड़े किये हैं, जो आज विश्व में मिसाल बने हुए हैं। भारत ने डिजिटल आइडेंटिटी का आधार मॉडल, रियल-टाइम फास्ट पेमेंट का यूपीआई मॉडल, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी), हेल्थ के क्षेत्र में ओपन हेल्थ सर्विस नेटवर्क, जैसे और भी मॉडल्स विकसित किए हैं।

- श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

अनुरूप कार्रवाई करने की व्यवस्था खड़ी करने के साथ ही साइबर सुरक्षा के मानक तैयार करने, एक दूसरे के बेहतरीन क्रियाकलापों को अपनाने और नियमन में तालमेल बनाने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर विचार करने को कहा। विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए 2019 से 2023 के बीच साइबर हमलों से दुनिया को लगभग 5.2 ट्रिलियन डॉलर के नुकसान की आशंका जताई गई है। उन्होंने फेक न्यूज, टूलकिट और दुष्प्रचार कैंपेन को रोकने और डायनामाइट से मेटावर्स और हवाला से क्रिप्टो करेंसी में बदल गई पारंपरिक चुनौतियों से निपटने के लिए साझा रणनीति बनाने पर बल दिया।

भारत में तकनीक और साइबर स्पेस का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, भारत जमीनी स्तर पर उभरती तकनीकों को अपनाने में अग्रणी रहा है और हमारा उद्देश्य समाज के सभी वर्गों के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को अधिक सुलभ और किफायती बनाना है। उन्होंने बताया कि पिछले 9 वर्षों में इन्टरनेट कनेक्शन में 250% की बढ़ोतरी हुई है और प्रति जीबी डाटा की लागत में 96% कमी आई है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत

थिंग्स' के साथ जोड़ा है।

सम्मेलन के दौरान डिजिटल अपराधों को काउंटर करने के लिए सभी देशों के कानूनों में एकरूपता लाने और साइबर अपराधों के सीमा रहित प्रकृति को देखते हुए देशों के अलग-अलग कानूनों के

भारत में 84 करोड़ लोग इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, साइबर स्पेस में सिक्योरिटी का चैलेंज बहुत बड़ा है। भारत के पास साइबर सिक्योरिटी का नंबर एक सिस्टम मौजूद है। न्यू इंडिया ने जिस तरह से पिछले 9 वर्षों में प्रौद्योगिकी और इंटरनेट का उपयोग करके भारत की दशकों पुरानी शासन की कहानी को एक आधुनिक, उत्तरदायी शासन में बदल दिया है, जो लोगों के जीवन को बदल रहा है, उसके लिए शेष विश्व के लिए एक प्रकाश स्तंभ की तरह है।

-श्री राजीव चंद्रशेखर, केंद्रीय उद्यमिता, कौशल विकास, इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री

500 मिलियन नए बैंक खाते खोले गए हैं और 330 मिलियन 'रुपे डेबिट कार्ड' वितरित किये गए हैं। भारत 2022 में 90 मिलियन लेन-देन के साथ वैश्विक डिजिटल भुगतान में अग्रणी रहा है और अब तक भारत में 35 ट्रिलियन रुपए के यूपीआई ट्रांजेक्शन हुए हैं। कुल वैश्विक डिजिटल भुगतान का 46% भारत में भुगतान हुआ है और 2017-18 से लेन-देन की मात्रा में 50 गुना बढ़ोत्तरी हुई है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के अंतर्गत, 52 मंत्रालयों में 300 से अधिक योजनाओं को कवर करते हुए, 300 मिलियन रुपए की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुँचाई गई है। डिजीलॉकर में लगभग 6 बिलियन डाक्यूमेंट्स स्टोर हैं। भारतनेट के तहत 6 लाख किलोमीटर की ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। एकीकृत मोबाइल एप्लिकेशन उमंग एप्प लाया गया, जिसमें 53 मिलियन रजिस्ट्रेशन्स हैं। सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी के इनिशिएटिव्स ने, एक दशक में भारत को एक 'डिजिटल राष्ट्र' में बदल दिया है।

श्री अमित शाह ने कहा कि साथ ही साइबर खतरों की संभावनाएँ भी बढ़ी हैं। उन्होंने इन्टरपोल की वर्ष 2022 की 'ग्लोबल ट्रेंड समरी रिपोर्ट' को उद्धत करते हुए कहा कि रैनसमवेयर, फिशिंग, ऑनलाइन घोटाले, ऑनलाइन बाल यौन-शोषण और हैकिंग जैसे साइबर अपराध की कुछ प्रवृतियां विश्वभर में गंभीर खतरे की स्थिति पैदा कर रही हैं और ऐसी संभावना है कि भविष्य में ये साइबर अपराध कई गुना और बढ़ेंगे। जी20 ने अब तक आर्थिक दृष्टिकोण से डिजिटल परिवर्तन और डेटा फ्लो पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अब अपराध और सुरक्षा को समझना और समाधान निकालना बेहद आवश्यक है।

हमारा प्रयास है कि एनएफटी, एआई, मेटावर्स तथा अन्य इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के युग में समावेशी और सहयोगात्मक तरीके से नए और

प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की जो मुहिम चला रखी है, उससे देश में इंटरनेट का उपयोग बढ़ा है। लोगों को सुविधा हो रही है। सरकार पेपरलेस काम पर जोर दे रही है। ऐसे में आईटी क्षेत्र बेहद अहम हो जाता है। इन दो दिनों में जिस प्रकार से साइबर सुरक्षा को लेकर विशेषज्ञों ने अपनी बातें रखी हैं, उसके बाद हर देश की सुरक्षा बेहद अहम है। दो दिनों के छह सत्रों में वर्तमान के साथ ही भविष्य को लेकर बात की गई। हमें भी अपने देश की साइबर सुरक्षा को लेकर पहले से अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। उद्घाटन सत्र में ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ही ने इस ओर ध्यान आकृष्ट कराया था। भारत डिजिटल युग में सामाजिक ताना-बाना को अक्षुण्ण रखना चाहता है। हमें इंटरनेट के दौर में सुरक्षित जीवन को लेकर आगे बढ़ना है। एआई को लेकर फेशियल रिकॉगनेशन काफी प्रचलित हो रहा है। हमें इसके हर पहलू पर निजता को देखते हुए काम करना होगा।

- श्री अजय मिश्रा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री

सम्मेलन में शामिल हुए लोग

सम्मेलन में जी20 सदस्य देशों, अफ्रीकी संघ और नौ अतिथि देशों बांग्लादेश, मिस्र, मॉरीशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों की भागीदारी देखी गई। अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरपोल और यूएनओडीसी ने भी अपने आधिकारिक प्रतिनिधि भेजे। अन्य उपस्थित लोगों में अनुसंधान संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और विभिन्न देशों, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे। सम्मेलन में भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों का भी स्वागत किया गया। कुल मिलाकर, सम्मेलन में लगभग 900 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

कोई भी देश या संगठन, अकेले साइबर खतरों का मुकाबला नहीं कर सकता है-इसके लिए एक संयुक्त मोर्चे की आवश्यकता है। हमारे भविष्य ने हमें यह अवसर दिया है कि हम संवेदनशीलता के साथ टेक्नोलॉजी का उपयोग करने और सार्वजनिक सुरक्षा तथा संरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अटल रहें और यह कार्य अकेले सरकारों द्वारा नहीं संभाला जा सकता है। हमारा लक्ष्य 'साइबर सक्सेस वर्ल्ड' का निर्माण करना है, न कि 'साइबर फेल्योर वर्ल्ड' का। साथ मिलकर हम, सभी के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध डिजिटल भविष्य सुनिश्चित करते हुए इन टेक्नोलॉजीज की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं।

- श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री

उभरते खतरों के लिए समय पर प्रतिक्रिया देकर हमें आगे रहना है। अपने वक्तव्य के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने डार्कनेट और मेटावर्स को युवाओं में कट्टरता फैलाने से लेकर आतंकी फंडिंग और ट्रेनिंग के लिए हो रहे इस्तेमाल को लेकर भी सचेत किया। साथ ही डार्कनेट पर चलने वाली इन गतिविधियों के पैटर्न को समझने और उससे निपटने के उपाय ढूंढ़ने के लिए सुरक्षा विशेषज्ञों से आह्वान किया। इसके लिए एक मजबूत और कारगर आपरेशनल सिस्टम बनाने के लिए साझा प्रयास की वकालत करते हुए उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन साइबर सुरक्षा की दिशा में एक ठोस एक्शन प्लान तैयार करने में सफल होगा। इससे पूर्व सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में ही केंद्रीय गृह सचिव, श्री अजय कुमार भल्ला ने कहा कि भारत ने चुनौती के महत्व को पहचानते हुए, जी20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर एक सम्मेलन आयोजित करके सक्रिय कदम उठाए।

भारत की ओर से शुरुआत की गई है और दुनिया के विशेषज्ञ अपने विचारों से इस समस्याओं को समग्रता में देखकर इसके निदान के लिए सुझाव देंगे। यकीनन, यह पूरी मानवता के लिए भगीरथी प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि यह सामूहिक जिम्मेदारी है कि सब मिलकर काम करें। भारत ने साइबर वॉलेंटियर्स के माध्यम से नया कदम उठाया है। डिजिटल तरीके से भविष्य को सुरक्षित करना हमारा कर्तव्य है। 13 और 14 जुलाई, 2023 को हुए सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय, दूरसंचार विभाग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अलावा इंटरपोल और ड्रग्स एवं अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यूएनओडीसी) के साथ मिलकर किया गया। सम्मेलन के अन्य भागीदारों में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया , नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु और अमृता विश्व विद्यापीठम शामिल रहे। सम्मेलन राष्ट्रीय राजधानी के पास गुरुग्राम में आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम उन 200 बैठकों में से एक था, जिसे भारत नई दिल्ली में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन की अगुवाई के हिस्से के रूप में आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। ■

साइबर सुरक्षित भारत बनाने के लिए

प्रतिबद्ध है सरकार

ब्यूरो

एनएफटी, एआई और मेटावर्स के युग में अपराध और सुरक्षा पर गुरुग्राम में आयोजित जी20 सम्मेलन के दौरान छह तकनीकी सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में वक्ताओं का उद्देश्य एनएफटी, एआई और मेटावर्स जैसी नई प्रौद्योगिकियों के युग में साइबर अपराध और सुरक्षा से उत्पन्न चुनौतियों को विस्तार से बताना और उसका समाधान करना रहा। वक्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया कि साइबर हमले हर स्तर पर गंभीर और जटिल चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। वैश्विक सहयोग पर जोर देते हुए विशेषज्ञों ने माना कि साइबर जागरूकता बढ़ाने और व्यक्तियों, संगठनों और समाज की सुरक्षा के लिए मजबूत नियम और डिजिटल बुनियादी ढांचे को तैयार करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

सम्मेलन के दौरान, जी20 देशों के प्रतिनिधियों, आमंत्रित देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य प्रतिभागियों ने इंटरनेट गवर्नेंस-डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, विस्तारित वास्तविकता, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी चुनौतियां और सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के आपराधिक उपयोग सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। यह स्वीकार करते हुए कि दुनिया पहले से कहीं अधिक डिजिटल रूप से जुड़ी हुई है, जो दुर्भावनापूर्ण ऑनलाइन अपराधियों के लिए भी अवसर प्रस्तुत करती है। यह व्यक्तियों, समाजों, व्यवसायों और सरकारों को नुकसान पहुंचाने के लिए नई प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हैं। प्रतिनिधियों ने एनएफटी, एआई और मेटावर्स प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग को रोकने के तरीकों और साधनों पर चर्चा की।

अफ्रीका से आई अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य और एआई अनुसंधान की सदस्य, सुश्री नन्ना नवाकनमा ने कहा कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय और भारतीय पुलिस की ओर से जरूरी विषय को लेकर एक बेहतर आयोजन किया गया है। वर्तमान में हर व्यक्ति को हर देश को एनएफटी, एआई और मेटावर्स की जानकारी होनी चाहिए। बीते 20 सालों में दुनिया तकनीक के स्तर पर काफी बदल गई है। इसलिए जरूरी है कि भविष्य में सभी देशों को एक साथ मिलकर साइबर सुरक्षा के लिए कदम बढ़ाने होंगे। भारत ने एक नई शुरुआत की है। हम सभी को मिलकर भारत के नेतृत्व में इस विषय पर काम करना चाहिए।

अपनी बात रखते हुए ऑस्ट्रेलिया के श्री पाब्लो लुइस हिनोजोसा अजाओला ने कौशल और प्रतिभा का मुद्दा उठाया। साइबर क्षेत्र को अभी भी कुशल प्रतिभा की आवश्यकता है। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में डिजिटल इंडिया की मुहिम बेहतर काम कर रही है। जी20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने साइबर सुरक्षा पर हम सभी को बात करने और इसे समझने का अवसर दिया है। महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है, लेकिन इन सुविधाओं का पूरी तरह से उपयोग करने के लिए आवश्यक प्रतिभा की कमी है। इसलिए, प्रतिभा के निर्माण और पोषण पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, विशेष रूप से 5 अरब से अधिक वैश्विक इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के साथ, जिनमें 3 अरब जी20 देशों से हैं। इस संदर्भ में आंतरिक सुरक्षा और प्रभावी शासन प्राप्त करने के लिए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।

अमेरिका की सुश्री एडविना फिट्जमौरिस ने साइबर स्पेस के तर्कसंगत विकास के लिए शासन और नवाचार के बीच संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने चिंता जताई कि अत्यधिक शासन और विनियमन वैश्विक नवाचार में बाधा बन सकते हैं। साइबर गतिविधियों में अधिक स्वतंत्रता की वकालत करते हुए, उन्होंने विनियमन और नवाचार के बीच एक तर्कसंगत संतुलन की अवधारणा पेश की।

अमेरिका के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, श्री दिमित्री श्वार्ट्समैन ने बताया कि बीते 3 वर्षों में औसतन साइबर हमलों का अनुपात निकाला जाए तो इसमें 742 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। फिशिंग, स्पूफिंग, नेटवर्क स्कैनिंग, डेटा उल्लंघन, सेवाओं में व्यवधान, वायरस संक्रमण, कोड हेरफेर, वेबसाइट हैकिंग- साइबर स्पेस अपराध के लिए एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, जो सीमाओं को पार कर रहा है और वैश्विक अनुपात ग्रहण कर रहा है। भारत साइबर अपराध से प्रभावित होने वाले शीर्ष पांच देशों में शामिल है। हालांकि केंद्रीय और राज्य एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं।

इजराइल सुरक्षा प्राधिकरण की पूर्व अध्यक्ष, सुश्री अनात शोशना गुएटा ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में अधिकार क्षेत्र और कानूनों की प्रयोज्यता के मुद्दे को संबोधित किया। वह साइबर अपराधों और विभिन्न प्रकार के अपराधों के लिए उचित कानूनों के अनुप्रयोग के बीच अंतर करने की आवश्यकता पर जोर देती है। उनका कहना था कि आकार-सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण पर्याप्त नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, सुश्री अनात ने जेनरेटिव एआई और वेब 3 में विकास के साथ-साथ विकेंद्रीकृत ऐप्स (डीएपी) के विकास के महत्व पर प्रकाश डाला, जो अक्सर एक ही प्राधिकरण के नियंत्रण से बाहर काम करते हैं।

सिंगापुर से जी20 सम्मेलन में आए इंटरपोल के तकनीकी और अनुसंधान प्रभाग के कार्यकारी निदेशक, श्री मदन मुरारी ओबरॉय ने एआई के कारण नौकरी विस्थापन की चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने नैतिक और मानवाधिकार निहितार्थों को संबोधित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि गोपनीयता अधिकार भी एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, विशेष रूप से लोकतांत्रिक समाजों में जहां कानून प्रवर्तन को सामान्य आबादी को प्रभावित करने वाले इन मुद्दों को जिम्मेदारी से संबोधित करना चाहिए। उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से हो रहे बाल यौन शोषण पर भी चिंता जताई और कहा कि इस पर अधिक फोकस होकर काम करना होगा। एआई, मेटावर्स जैसी समस्याओं और उसके कानूनी पक्ष को लेकर चिंता जताते हुए सभी देशों से मिलकर काम करने को कहा।

अमेरिका में नासा के मुख्य सलाहकार, डॉ. उमर हातमलेह ने एआई के तेजी से विकास पर प्रकाश डाला। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों के बीच घनिष्ठ सहयोग का आग्रह किया। हालांकि, उन्होंने एआई में लोकतंत्र की कमी के बारे में चिंता व्यक्त की और नवाचार और प्रसार में जोखिम लेने की सलाह दी। फिर भी, उन्होंने समाज को बेहतर बनाने के लिए एआई की क्षमता को पहचाना और प्रवर्तन प्रणालियों को मजबूत करने के लिए नवीन तंत्र का आह्वान किया।

अमेरिका के डार्कऑल कंपनी के सीईओ एवं सह-संस्थापक, श्री मार्क टिमोथी टर्नएज ने उल्लेख किया कि डार्क नेट की उत्पत्ति गैर-दुर्भावनापूर्ण थी, लेकिन अब यह मुख्य रूप से आपराधिक

गतिविधियों से जुड़ा है, इसका 95 प्रतिशत उपयोग आपराधिक है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से आतंकवादी संगठनों को दान देने के लिए डार्क नेट के उपयोग पर प्रकाश डाला। इस समस्या के समाधान के लिए, भुगतान गेटवे पर वास्तविक मुद्राओं के लिए क्रिप्टो करेंसी का आदान-प्रदान करते समय नियमों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर प्रो.अशोक झुनझुनवाला, एसोसिएट प्रोफेसर अभिषेक परूई सहित आईआईटी दिल्ली के सहायक प्रोफेसर अरुण बालाजी बुडरू ने हो रहे साइबर अपराध और उसकी सुरक्षा को

लेकर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया। साइबर फिजिकल सिस्टम में प्रौद्योगिकी नवाचार (टीआईपीएस) में अनुसंधान और प्रौद्योगिकी अनुवाद में वृद्धि और उद्योग और अन्य स्रोतों से बढ़ी हुई फंडिंग का उपयोग करने के लिए सिस्टम में क्षमता विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि दुनिया भर में आदर्श बनने के साथ प्रौद्योगिकी पर भारी निर्भरता अपरिहार्य थी। इसके अलावा, 5जी को अपनाने में वृद्धि, उपकरणों की परस्पर कनेक्टिविटी, नई प्रक्रियाएं और प्रक्रियाए, अद्यतन कर्मचारी प्रोफाइल और कम-नियंत्रित कार्य वातावरण सभी पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

सी20 के शेरपा एवं पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव के विशेष सलाहकार, श्री विजय नांबियार ने कहा कि 40 प्रतिशत साइबर हमले राज्य संस्थानों को निशाना बनाते हैं। अपराधी अपनी अवैध गतिविधियों के लिए एआई का भारी उपयोग करते हैं, जिससे यह एक लाभदायक उद्योग बन जाता है। उन्होंने देशों के बीच साइबर समन्वय के लिए बुडापेस्ट कन्वेंशन के प्रभावी उपयोग का सुझाव दिया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य, श्री राजीव जैन ने अपनी बात रखते हुए कहा कि इंटरनेट से क्रांतिकारी बदलाव आए हैं लेकिन अब व्यक्तिगत गोपनीयता सहित कई मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के लिए साइबर स्पेस का दुरुपयोग किया जा रहा है। इसलिए, साइबर सुरक्षा साइबर अपराध से लड़ने और मानवाधिकारों को संरक्षित करने की कुंजी है। बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं। भारत ने बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि हम बेकार बैठकर यह नहीं कह सकते कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं। इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। कंटेंट होस्ट और पीयर-टू-पीयर एन्क्रिप्टेड संचार को सक्षम करने वाले मध्यस्थों को यह जांचने की आवश्यकता है कि और क्या किया जा सकता है।

सम्मेलन में आतंकवादी उद्देश्यों के लिए राज्य और गैर-राज्य अभिकर्त्ता द्वारा आईसीटी के उपयोग को रोकने के महत्व पर जोर दिया गया। इसने साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, सूचना साझा करने और पारस्परिक कानूनी सहायता की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। एआई के लिए पारदर्शी और जवाबदेह शासन ढांचे पर भी चर्चा की गई। सम्मेलन में व्यक्तियों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को ऑनलाइन शोषण से बचाने के लिए एक खुले, सुरक्षित और शांतिपूर्ण आईसीटी वातावरण की आवश्यकता पर बल दिया गया। निरंतर खतरों का मुकाबला करने और आईसीटी अपराधों पर व्यापक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन स्थापित करने के महत्व पर भी जोर दिया गया।■

सभी फोटो: पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो/ केंद्रीय गृह मंत्रालय

साइबर सुरक्षा: भारत के विकास में है अहम भूमिका

प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर गृह मंत्रालय कर रहा काम

ब्यूरो

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब सुरक्षा की बात होती है, तो साइबर सुरक्षा अनिवार्य रूप से उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इसके आर्थिक और भू-वैज्ञानिक जटिलताओं के कारण इस पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में जी20 के मंच पर साइबर सुरक्षा पर अधिक फोकस, सूचना के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और डिजिटल पब्लिक प्लेटफार्मों की सुरक्षा और अभेद्यता सुनिश्चित करने में सकारात्मक योगदान को लेकर भारत ने नई शुरुआत की है। सरकार भारत में सुरक्षित साइबर माहौल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जी20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के पास अब एक सुरक्षित साइबर स्पेस का निर्माण करने और साइबर सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को प्राथमिकता देने के लिए एक वैश्विक साझेदारी की अगुवाई करने का मौका है, जिसका बेहतर निर्वहन सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी की पहल पर केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार काम कर रहा है। आज के युग में साइबर सुरक्षा का भारत के विकास में अहम रोल है। एक सुरक्षित साइबर स्पेस की आवश्यकता बेहद अहम है, क्योंकि साइबर स्पेस से जुड़े खतरों की संख्या और उनके अलग-अलग तरीकों में तेजी के साथ बढ़ोतरी हुई है, विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े खतरों को लेकर। हाल ही में इंटरपोल द्वारा जारी 'ग्लोबल ट्रेंड समरी रिपोर्ट 2022' के अनुसार, दुनिया भर में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ साइबर खतरों की संभावनाएं बढ़ी हैं और अलग-अलग रूप ले चुकी

> **भारत सरकार ने 'साइट्रेन' पोर्टल नामक एक विशाल खुला ऑनलाइन पाठ्यक्रम मंच भी बनाया है, जो शायद साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा। देश के सभी पुलिस स्टेशनों में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) लागू किया गया है। भारत सरकार ने साइबर अपराध के खिलाफ व्यापक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए भारतीय साइबर-अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है।**
>
> **- श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

किसी अपराध को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से एक-दूसरे के साथ सभी देश सहयोग करते हैं, वैसा ही तालमेल साइबर सुरक्षा के लिए भी रखना होगा। नई-नई तकनीक से साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रतिदिन चुनौतियां पैदा हो रही हैं। साइबर सुरक्षा को लेकर चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना होगा। समाधान को आपस में साझा करना होगा।

-श्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

हैं। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि रैंसमवेयर, फिशिंग, ऑनलाइन घोटाले, ऑनलाइन बाल यौन शोषण और हैकिंग जैसे साइबर अपराध के रुझान विश्व स्तर पर गंभीर खतरे पैदा करते हैं और समाज में व्यवस्था बनाए रखने के प्रयासों को चुनौती देते हैं। इन चिंताओं पर दिल्ली में जी 20 सम्मेलन में भारत के नेतृत्व में इन चिंताओं पर विचार विमर्श हुआ और इससे निपटने के उपायों पर चर्चा की। इस चर्चा में गृह मंत्री ने भारत की तैयारियों के बारे में बताया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने आगाह किया कि जी20 ने आर्थिक दृष्टिकोण से डिजिटल परिवर्तन और डेटा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अपराध और सुरक्षा के पहलुओं को समझना और समाधान ढूंढ़ना महत्वपूर्ण है। उन्होंने एनएफटी, एआई और मेटावर्स जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के युग में अपराधियों से आगे रहने और समन्वित तरीके से नए और उभरते खतरों का जवाब देने की आवश्यकता पर जोर दिया।

श्री अमित शाह ने साइबर सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। एक समान साइबर रणनीति की रूपरेखा तैयार की गई है, साइबर अपराधों की वास्तविक समय पर रिपोर्टिंग स्थापित की गई है और कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) की क्षमता निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। भारतीय साइबर-अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) की स्थापना साइबर अपराध के खिलाफ व्यापक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने 'साइट्रेन' पोर्टल लॉन्च किया है, जो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़े पैमाने पर ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य कुशल कार्यबल का निर्माण करना है।

साइबर दुनिया की वैश्विक प्रकृति को देखते हुए, प्रतिनिधियों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया गया कि साइबर खतरों से निपटने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों दृष्टिकोणों की आवश्यकता है। शब्द 'ग्लोकल' (वैश्विक प्लस स्थानीय) इस विचार को समाहित करता है कि साइबर सुरक्षा में समस्याओं और समाधानों के लिए वैश्विक और स्थानीय प्रयासों के संयोजन की आवश्यकता होती है। आतंकवाद, आतंकी वित्त पोषण, कट्टरपंथ, नार्को-आतंकवाद लिंक और गलत सूचना सहित उभरती चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की क्षमताओं को मजबूत करने का आह्वान किया।

दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान एक महत्वपूर्ण चिंता जो उभर कर सामने आई है, वह है साइबर दुनिया में आतंकवादियों की घुसपैठ। अन्य व्यक्तियों की तरह, आतंकवादी भी अपने नेटवर्क का विस्तार करने के लिए डिजिटल स्थान का उपयोग कर रहे हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने इस मुद्दे को स्वीकार करते हुए कहा कि आतंकवादी हिंसा करने, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और वित्तीय संसाधन जुटाने के नए तरीके ढूंढ़ रहे हैं। आभासी संपत्ति और डार्कनेट वित्तीय लेन-देन और कट्टरपंथी सामग्री फैलाने के लिए आतंकवादियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण बन गए हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को इन दोषियों को पकड़ने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डार्कनेट ब्राउजर आतंकवादियों की पहचान की रक्षा करते हैं।

साइबर युद्ध में, लक्ष्य अब केवल भौतिक संसाधनों तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ऑनलाइन संचालित करने की हमारी क्षमता तक विस्तारित हैं। भौतिक सीमाएँ उन्हें ऑनलाइन अपराध करने से नहीं रोकतीं। ऑनलाइन नेटवर्क में व्यवधान, यहां तक कि थोड़े समय के लिए भी, भयावह परिणाम हो सकते हैं और तबाही मचा सकते हैं। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार, 2019 और 2023 के बीच साइबर हमलों से दुनिया भर में लगभग 5.2 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। दुर्भावनापूर्ण तत्वों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग पता लगाने और रोकथाम को और जटिल बना देता है। गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने सीमा पार साइबर अपराधों की जांच के लिए समन्वय, सूचना साझाकरण और संयुक्त प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों को नियंत्रित करने के लिए एक पारदर्शी और जवाबदेह ढांचे का निर्माण, जिम्मेदार प्रौद्योगिकी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षा उपायों को मजबूत करना दुनिया भर की

मोबाइल फोन/टैब-सुरक्षा टिप्स

मोबाइल फोन, जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। व्यक्तिगत और संगठन के डाटा की सुरक्षा के लिए फोन का सुरक्षित इस्तेमाल जरूरी है। मोबाइल के दुरुपयोग से आंकड़ों की चोरी, वित्तीय हानि, अनाधिकृत एक्सेस, मैलवेयर संक्रमण आदि हो सकते हैं।

क्या करें

- सार्वजनिक वाई-फाई से सावधान रहें, सार्वजनिक नेटवर्क पर साझा की गई जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है।
- स्मार्टफोन, मोबाइल एप्लिकेशन और सोशल मीडिया एकाउंट की डिफॉल्ट प्राइवेसी सेटिंग्स पर गौर करें।
- पब्लिक दृश्यता विकल्प के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई व्यक्तिगत तस्वीरों का दुरुपयोग किया जा सकता है।
- किसी ऐप को डाउनलोड करने से पहले उसकी प्रतिष्ठा/प्रामाणिकता की जांच करें।
- ऐप डाउनलोड करने से पहले विक्रेता की गोपनीयता नीतियां पढ़ें और ऐप परमिशन को सत्यापित करें।
- विश्वस्त स्त्रोतों से ही मोबाइल ऐप डाउनलोड करने को प्राथमिकता दे।
- अनावश्यक ऐप बंद कर दें/हटा दें।
- टेलीकॉम ऑपरेटरों के साथ डू नॉट डिस्टर्ब के लिए पंजीकरण करें।
- बच्चों या नाबालिगों को मोबाइल फोन देते हुए पेरेंटल कंट्रोल मोड का प्रयोग करें।
- गोपनीय आंकड़ों की सुरक्षा के लिए डिवाइस/एसडी कार्ड क्रिप्शिन का प्रयोग करें।
- अपने डिवाइस को एक मजबूत पिन/पासवर्ड या बायोमीट्रीक के साथ सुरक्षित रखें और मोबाइल फोन में ऑटो लॉक की सेटिंग इनेबल करें।
- हमेशा डाटा, जैसे संपर्क, व्यक्तिगत, फोटो आदि का बैकअप रखें।

क्या ना करें

- अपरिचितों द्वारा एसएमएस, ई-मेल या चैट मैसेज के माध्यम से भेजे गए लिंक का जवाब न दें अथवा उस पर क्लिक ना करें।
- डिवाइस में किसी प्रकार का व्यक्तिगत संवेदनशील डाटा जैसे- टैक्स, वीडियो, फोटोग्राफ आदि स्टोर न करें
- पब्लिक वायरलैस नेटवर्क का प्रयोग करते हुए अकाउंट में, खास तौर से वित्तीय अकाउंट में लॉगिन न करें।

सामान्य कंप्यूटर उपयोग

कंप्यूटर सुरक्षा क्या है?

कंप्यूटर सिस्टम की सुरक्षा, सूचना की चोरी और अनाधिकृत पहुंच से बचाव, कंप्यूटर सुरक्षा है। यह कंप्यूटर सिस्टम के अनाधिकृत प्रयोग की रोकथाम और उसका पता लगाने की प्रक्रिया है।

कंप्यूटर सुरक्षा को खतरा

कंप्यूटर सुरक्षा खतरे वे संभावित खतरे हैं, जो कंप्यूटर के सामान्य कामकाज में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ सामान्य और हानिकारक कंप्यूटर खतरे हैं-कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर ट्रोजन, फिशिंग मेल/यूआरएल, बोटनेट, कीलॉगर।

क्या करें

- हमेशा विश्वसनीय स्त्रोतों से एप्लिकेशन/सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें।
- ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लिकेशन और एंटी-वायरस सॉफ्टवेयर को नियमित रूप से अपडेट करें।
- महत्वपूर्ण डेटा/फाइलों/दस्तावेजों का नियमित अंतराल पर बैकअप सुनिश्चित करें।
- उपयोग न होने पर कंप्यूटर स्क्रीन लॉक रखें।
- कंप्यूटर फायरवॉल को हमेशा ऑन रखें।
- सिस्टम पर कम सुविधा वाले खाते उपयोग करें।
- हमेशा जेन्युइन /लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन के उपयोग को प्राथमिकता दें।
- वेबसाइटों, ई-मेल या यूएसबी से डाउनलोड की गई सभी फाइलों / सामग्री को स्कैन करें।
- अनावश्यक प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करें।

क्या न करें

- कंप्यूटर सिस्टम पर चल रहे किसी भी अवांछित प्रोग्राम की पहचान करने के लिए टास्क मैनेजर का प्रयोग करें।
- सर्वर तक पहुंच की अनुमति, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के माध्यम से होनी चाहिए।
- प्रयोग में न होने पर रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन और नेटवर्क फाइल शेयरिंग बंद कर दें।
- नियमित अपडेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट सेटिंग्स को ऑटो डाउनलोड विकल्प पर सेट करें।

क्या ना करें

- कभी भी सॉफ्टवेयर /एप्लिकेशन की पायरेटेड कॉपी इंस्टॉल न करें और न ही उनका इस्तेमाल करें। इनमें मैलवेयर हो सकता है।
- password@123, आदि जैसे अनुमान योग्य/कमजोर पासवर्ड का प्रयोग न करें।
- अविश्वसनीय/अप्रत्याशित पॉप-अप विज्ञापनों/प्रोग्राम पर क्लिक न करें।
- डेटा को निकाले और मिटाए बिना कंप्यूटर या हार्ड ड्राइव का निपटान न करें।

सामान्य इंटरनेट सुरक्षा सावधानियां

इंटरनेट के आविष्कार ने संचार और सूचना को साझा करने के तरीके में क्रांति ला दी है। हालांकि, इंटरनेट का असुरक्षित इस्तेमाल किसी संगठन के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। इंटरनेट सुरक्षा में ब्राउजर सुरक्षा, वेबसाइट सुरक्षा, सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन आदि शामिल हैं। इनका उद्देश्य, इंटरनेट पर हमलों के विरुद्ध नियमों और उपायों को लागू करना है। इंटरनेट के असुरक्षित इस्तेमाल से फिशिंग, ऑनलाइन वायरस, ट्रोजन, वर्म्स, रैंसमवेयर, व्यावसायिक ईमेल संबंधी क्षति, वित्तीय नुकसान आदि जोखिम हो सकते हैं।

क्या करें

- **संदिग्ध लिंक/यूआरएल क्लिक/डाउनलोड करते समय चौकस रहें**
- **गोपनीय गतिविधियों/ लेनदेन के बाद ब्राउजर हिस्ट्री को समाप्त करने की आदत डालें**
- **क्लाउड स्टोरेज का प्रयोग उपयुक्त सुरक्षा / गोपनीयता सेटिंग्स के साथ करें**
- **कोई भी सूचना साझा करने से पहले सोशल मीडिया प्रोफाइल की प्रामाणिकता और पहचान सत्यापित करें**
- **उन सेवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग करें, जिनके लिए लोकेशन की जानकारी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जीपीएस कॉरडिनेट्स वाली फोटो पोस्ट करने से बचें**

क्या ना करें

- **ऑनलाइन शॉपिंग, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई आदि जैसे वित्तीय लेनदेन के लिए किसी भी सार्वजनिक कंप्यूटर या वाई-फाई का प्रयोग न करें**
- **अविश्वसनीय और असुरक्षित वेबसाइट पर ई-मेल पता, फोन नंबर, भुगतान कार्ड आदि का विवरण न दें**
- **सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर असत्यापित सामग्री पर भरोसा न करें और इसे साझा न करें। साझा करने से पहले हमेशा स्त्रोत और सामग्री की प्रामाणिकता जांच लें**

प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के लिए आवश्यक है।

जैसे-जैसे डिजिटल मुद्रा से जुड़े साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, वित्तीय अनियमितताओं को रोकने के लिए राष्ट्रों के बीच एक समर्पित आम चैनल स्थापित करना महत्वपूर्ण हो गया है। एनएफटी प्लेटफार्मों के तृतीय-पक्ष सत्यापन से विश्वास बढ़ सकता है और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लग सकता है। उभरते खतरों से निपटने के लिए कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों (सीईआरटी) को मजबूत करना और पूर्वानुमानित, निवारक, सुरक्षात्मक और पुनर्प्राप्ति कार्यों के लिए 24x7 साइबर सुरक्षा तंत्र स्थापित करना अत्यावश्यक है। बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों को अतिरिक्त सतर्क रहना होगा, क्योंकि उनका लेनदेन राष्ट्रीय सीमाओं से परे भी होता है। इसलिए, साइबर खतरों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राष्ट्रों, संगठनों और हितधारकों के बीच सहयोग और सूचना साझा करना महत्वपूर्ण है। सुरक्षित साइबरस्पेस के लिए विभिन्न देशों के कानूनों में एकरूपता और विभिन्न कानूनी ढांचे के तहत प्रतिक्रिया तंत्र की स्थापना आवश्यक है। उद्योग और शिक्षा जगत के सहयोग से सदस्य देशों के बीच वास्तविक समय में साइबर खतरे की खुफिया जानकारी साझा करना महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त, एक पारदर्शी और जवाबदेह शासन ढांचे के निर्माण के माध्यम से एआई सहित उभरती प्रौद्योगिकियों का जिम्मेदार उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जी20 द्वारा वकालत की गई साइबर सुरक्षा के लिए एक नवीनीकृत वैश्विक प्रतिबद्धता आवश्यक है और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने साइबर-विफल दुनिया के बजाय साइबर-सफल दुनिया बनाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। ■

जी20 सम्मेलन के दौरान केंद्रीय गृह सचिव, श्री अजय कुमार भल्ला अध्यक्षीय सारांश जारी करते हुए।

चंद्रयान-3 से देश की आशाओं को लगेंगे पंख

> **चंद्रयान-3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नया अध्याय लिखा है। यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को ऊपर उठाते हुए ऊंची उड़ान भरता है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों के अथक समर्पण का प्रमाण है। मैं उनकी भावना और प्रतिभा का अभिनंदन करता हूं।**
>
> **-श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

ब्यूरो

विज्ञान और वैज्ञानिकों की बदौलत भारत अंतरिक्ष में बुलंदियां हासिल कर रहा है। इसका ताजा उदाहरण है चंद्रयान-3। 14 जुलाई 2023 हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में अंकित रहेगा। देश का तीसरा मिशन चंद्रयान-3 अपनी यात्रा पर निकल गया है। यह मिशन हमारे देश की आशाओं और सपनों को आगे बढ़ाएगा। 3,00,000 किमी से अधिक की दूरी तय करते हुए, यह आने वाले हफ्तों में चंद्रमा पर पहुंचेगा। चंद्रयान पर मौजूद वैज्ञानिक उपकरण चंद्रमा की सतह का अध्ययन करेंगे और हमारे ज्ञान को बढ़ाएंगे।

चंद्रयान-3 के सफल लॉन्च को भारत की उम्मीदों और सपनों की उड़ान बताते हुए प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह दिन अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्वर्णाक्षरों में दर्ज किया जाएगा। इसरो जैसे ही चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग कराने में कामयाब होगा, भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला चौथा देश बन जाएगा।

> **भारत ने चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण के साथ अपनी ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा शुरू की। इसरो के वैज्ञानिकों को मेरी हार्दिक बधाई। उनकी अथक खोज ने भारत को पीढ़ियों के लिए एक उल्लेखनीय अंतरिक्ष यात्रा की पटकथा लिखने की राह पर आगे बढ़ाया है।**
>
> **- श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री**

प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों को धन्यवाद, अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत का इतिहास बहुत समृद्ध है। चंद्रयान-1 को वैश्विक चंद्र मिशनों में एक पथ प्रदर्शक माना जाता है, क्योंकि इसने चंद्रमा पर जल के अणुओं की उपस्थिति की पुष्टि की है। यह दुनिया भर के 200 से अधिक वैज्ञानिक प्रकाशनों में प्रकाशित हुआ। चंद्रयान-1 तक, चंद्रमा को एक पूर्ण रूप शुष्क, भू-वैज्ञानिक रूप से निष्क्रिय और निर्जन खगोलीय पिंड माना जाता था। अब इसे जल और इसकी उप-सतह पर बर्फ की उपस्थिति के साथ एक गतिशील और भू-वैज्ञानिक रूप से सक्रिय खगोलीय खंड के रूप में देखा जाता है। हो सकता है कि भविष्य में इस पर संभावित रूप से निवास किया जा सके।

चंद्रयान-2 भी उतना ही महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे जुड़े ऑर्बिटर के डेटा ने पहली बार रिमोट सेंसिंग के माध्यम से क्रोमियम, मैंगनीज और सोडियम की उपस्थिति का पता लगाया था। इससे चंद्रमा के मैगनेटिक विकास के बारे में अधिक जानकारी भी मिलेगी। चंद्रयान 2 के प्रमुख वैज्ञानिक परिणामों में चंद्र सोडियम के लिए पहला वैश्विक मानचित्र, क्रेटर आकार वितरण पर उन्नत जानकारी, आईआईआईआरएस उपकरण के साथ चंद्र सतह पर जल से निर्मित बर्फ का स्पष्ट रूप से पता लगाना और बहुत कुछ शामिल है। यह मिशन लगभग 50 प्रकाशनों में प्रकाशित हुआ है। ■

सम्मान और साझेदारी की उड़ान

सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर' से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी

ब्यूरो

फ्रांस के राष्ट्रपति, श्री इमैनुएल मैक्रों ने प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी को 'ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर' से सम्मानित किया। यह सैन्य या नागरिक सम्मानों में सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है। प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने इस अद्वितीय सम्मान के लिए राष्ट्रपति, श्री मैक्रों को धन्यवाद दिया। इससे पूर्व दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति, नेल्सन मंडेला, वेल्स के तत्कालीन राजकुमार, किंग चार्ल्स, जर्मनी के पूर्व चांसलर, एंजेला मर्केल को भी यह सम्मान मिल चुका है।

फ्रांस द्वारा दिया गया यह सम्मान प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी को विभिन्न देशों द्वारा दिए गए शीर्ष अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों की श्रृंखला में एक और सम्मान है। इनमें जून 2023 में मिस्र द्वारा ऑर्डर ऑफ द नाइल, मई 2023 में पापुआ न्यू गिनी द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, मई 2023 में कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, मई 2023 में पलाऊ गणराज्य द्वारा एबाकल पुरस्कार शामिल हैं। 2021 में भूटान द्वारा ड्रुक ग्यालपो, 2020 में अमेरिकी सरकार द्वारा लीजन ऑफ मेरिट, 2019 में बहरीन द्वारा किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां, 2019 में मालदीव द्वारा ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन, 2019 में रूस द्वारा ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू पुरस्कार। 2019 में यूएई द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद अवॉर्ड, 2018 में ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवॉर्ड, 2016 में अफगानिस्तान द्वारा स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान और 2016 में सउदी अरब द्वारा ऑर्डर ऑफ अब्दुलअजीज अल सऊद।

दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, वेल्स के तत्कालीन राजकुमार किंग चार्ल्स, जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को भी यह सम्मान मिल चुका है।

इससे पहले जब प्रधानमंत्री अपनी राजकीय यात्रा के दौरान पेरिस पहुंचे तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपने आधिकारिक निवास एलिसी पैलेस में एक निजी रात्रि भोज के लिए प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की। वहां उनका स्वागत फ्रांस के राष्ट्रपति, इमैनुएल मैक्रों और फ्रांस की प्रथम महिला, ब्रिगिट मैक्रों ने किया। प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने 13 जुलाई, 2023 को फ्रांस की प्रधानमंत्री महामहिम सुश्री एलिजाबेथ बोर्न से मुलाकात की। 14 जुलाई, 2023 को प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की नेशनल असेंबली की अध्यक्ष, सुश्री येल ब्रौन पिवेट और असेंबली के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के साझा मूल्यों को रेखांकित किया। उन्होंने दोनों देशों की संसदों के बीच सहयोग को और अधिक बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। फ्रांस ने भारत की व्यापक निर्वाचन प्रक्रिया की प्रशंसा की। फ्रांस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात के शहजादे, शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। 2015 के बाद से खाड़ी देश की अपनी पांचवीं यात्रा के दौरान वे यूएई के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक, शेख खालिद मोहम्मद विन जायद अल नाह्यान से द्विपक्षीय वार्ता में कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने इससे पहले 2015, 2018, 2019 और 2022 में अरब देश की यात्रा की थी। खास बात यह है कि भारत, यूएई का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और द्विपक्षीय व्यापार 84 अरब डॉलर से अधिक का है। प्रधानमंत्री ने 15 जुलाई, 2023 को अबू धाबी में प्रतिनिधिमंडल स्तर और आमने-सामने की वार्ता में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। दोनों राजनेताओं ने व्यापार और निवेश, फिनटेक, ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, उच्चतर शिक्षा और लोगों के परस्पर संबंधों सहित द्विपक्षीय साझेदारी के विभिन्न आयामों पर व्यापक चर्चा की। प्रधानमंत्री ने अबू धाबी में सीओपी 28 के मनोनीत अध्यक्ष और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के ग्रुप सीईओ, डॉ. सुल्तान अल जाबेर से मुलाकात की। यूएई की अध्यक्षता में यूएनएफसीसीसी के आगामी सीओपी 28 पर विचार-विमर्श किया गया। डॉ. जाबेर ने प्रधानमंत्री को इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए यूएई के दृष्टिकोण से अवगत कराया। ■

भारत को जोड़ती है गीता प्रेस

ब्यूरो

जब किसी संस्था का उद्देश्य होता है राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण और मानवता का मार्गदर्शन, तो वो देश को जोड़ती है। साथ ही देश की एकजुटता को सशक्त करती है। ऐसी संस्था है गीता प्रेस। 7 जुलाई को गीता प्रेस ने अपना शताब्दी महोत्सव मनाया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1923 में गीता प्रेस के रूप में यहां जो आध्यात्मिक ज्योति प्रज्ज्वलित हुई थी, आज उसका प्रकाश पूरी मानवता का मार्गदर्शन कर रहा है। यह अत्यंत सौभाग्यशाली मौका है जब यहां मौजूद लोग इस मानवीय मिशन की शताब्दी के साक्षी बने। इस ऐतिहासिक अवसर पर वर्तमान सरकार ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार भी दिया है।

प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी बताते हैं कि गीता प्रेस ने अपने सौ वर्षों की ये यात्रा एक ऐसे समय में पूरी की है, जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है। इस तरह के योग केवल संयोग नहीं होते। 1947 के पहले भारत ने निरंतर अपने पुनर्जागरण के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में प्रयास किए। अलग-अलग संस्थाओं ने भारत की आत्मा को जगाने के लिए आकार लिया। इसी का परिणाम था कि 1947 आते-आते भारत मन और मानस से गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हो गया। गीता प्रेस की स्थापना भी इसका एक बहुत बड़ा आधार बनी। सौ साल पहले का ऐसा समय जब सदियों की गुलामी ने भारत की चेतना को धूमिल कर दिया था। आप भी जानते हैं कि इससे भी सैकड़ों साल पहले विदेशी आक्रांताओं ने हमारे पुस्तकालयों को जलाया था। अंग्रेजों के दौर में गुरुकुल और गुरु परंपरा लगभग नष्ट कर दिये गए थे। ऐसे में स्वाभाविक था कि ज्ञान और विरासत लुप्त होने की कगार पर थे। हमारे पूज्य ग्रंथ गायब होने लगे थे। जो प्रिंटिंग प्रेस भारत में थे, वो महंगी कीमत के कारण सामान्य जन की पहुंच से दूर थे। आप कल्पना करिए, गीता और रामायण के बिना हमारा समाज कैसे चल रहा होगा? जब मूल्यों और आदर्शों के स्रोत ही सूखने लगें, तो समाज का प्रवाह अपने आप थमने लगता है। भारत की अनादि यात्रा में ऐसे कितने ही पड़ाव आए हैं, जब हम और ज्यादा परिष्कृत होकर के निकले हैं। कितनी ही बार अधर्म और आतंक बलवान हुआ है, कितनी ही बार सत्य पर संकट के बादल मंडराए हैं, लेकिन तब हमें श्रीमद भागवत गीता से ही सबसे बड़ा विश्वास मिलता है-'यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यहम'॥

बीते 100 वर्षों में गीता प्रेस द्वारा करोड़ों किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं। गीता प्रेस, भारत को जोड़ती है, भारत की एकजुटता को सशक्त करती है। देशभर में इसकी 20 शाखाएं हैं। देश के हर कोने में रेलवे स्टेशनों पर हमें गीताप्रेस का स्टॉल देखने को मिलता है। 15 अलग-अलग भाषाओं में यहां से करीब 16 सौ प्रकाशन होते हैं। गीता प्रेस अलग-अलग भाषाओं में भारत के मूल चिंतन को जन-जन तक पहुंचाती है। गीता प्रेस एक तरह से 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना को प्रतिनिधित्व देती है। प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि गांधी जी का भी गीता प्रेस से भावनात्मक जुड़ाव था। एक समय में, गांधी जी, कल्याण पत्रिका के माध्यम से गीता प्रेस के लिए लिखा करते थे। उस समय गांधी जी ने ही सुझाव दिया था कि कल्याण पत्रिका में विज्ञापन न छापे जाएं। कल्याण पत्रिका आज भी गांधी जी के उस सुझाव का शत-प्रतिशत अनुसरण कर रही है। ■

> **मेरा गोरखपुर का दौरा, 'विकास भी, विरासत भी' इस नीति का एक अद्भुत उदाहरण है। मुझे अभी चित्रमय शिव पुराण और नेपाली भाषा में शिव पुराण के विमोचन का सौभाग्य मिला है।**
>
> **-श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री**

आपदा प्रतिरोधी तंत्र विकसित करना हमारी प्राथमिकता

ब्यूरो

आपदा कभी भी आ सकती है। इसके लिए हर पल सतर्क रहना होगा। ऐसा काम केंद्र सरकार कर रही है। आपदा के समय केंद्र सरकार राज्यों के लिए हर तरह से तैयार रहती है। त्वरित आधार पर सहायता पहुंचाई जाती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय तुरंत की आपदा राहत के लिए एनडीआरएफ को घटना स्थल पर भेजती है। जरूरत पड़ने पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल को भी मोर्चे पर लगाया जाता है। इसके साथ ही आर्थिक रूप से भी सहायता की जाती है। इसकी बानगी मिलती है हाल ही में हिमाचल में आई बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन की घटना से। ऐसी घटनाएं प्राकृतिक हैं। इन्हें रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुशलतापूर्वक इनसे उबरा जरूर जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में अचानक आई बाढ़/बादल फटने और भूस्खलन के कारण उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए, भारत सरकार ने कुशलतापूर्वक निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को सभी आवश्यक रसद और वित्तीय सहायता प्रदान की है। 11 टीमें बचाव अभियान के लिए बचाव नौकाओं और अन्य आवश्यक उपकरणों के साथ एनडीआरएफ को तैनात किया गया है। नागरिक निकासी के लिए पैरा स्पेशल फोर्सेस और 205 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन को पोंटा साहिब में तैनात किया गया है। निकासी मिशन के लिए दो एमआई-17वी5 हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के केंद्रीय हिस्से की दूसरी किस्त की हिमाचल प्रदेश को अंतरिम राहत के रूप में वर्ष 2023-24 के लिए ₹180.40 करोड़ अग्रिम राशि जारी करने को मंजूरी दे दी है। इस राज्य के प्रभावित लोगों की मदद देने के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही तत्काल प्रकृति के राहत उपायों के लिए 10 जुलाई 2023 को एसडीआरएफ से हिमाचल प्रदेश को ₹180.40 करोड़ की केंद्रीय हिस्सेदारी की पहली किस्त जारी कर दी है। धनराशि जारी होने से राज्य सरकार को चालू मानसून सीजन के दौरान प्रभावित लोगों को राहत उपाय करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों और स्थिति का मौके पर आकलन करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों (आईएमसीटी) का भी गठन किया है।

बात यहीं समाप्त नहीं होती। हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा भारत में कहीं भी घट सकती है। भारत के हर राज्य की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप आपदा का रूप अलग हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फंड (एसडीआरएफ) के तहत 19 राज्य सरकारों को ₹6,194.40 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी। इस राशि में वर्ष 2022-23 के लिए 4 राज्यों (छत्तीसगढ़, मेघालय, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश) को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹1,209.60 करोड़ और 15 राज्यों (आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा) को वर्ष 2023-24 के लिए ₹4,984.80 करोड़ शामिल हैं। इस धनराशि का उपयोग राज्य मौजूदा मानसून सीजन के दौरान राहत उपायों के लिए कर सकेंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पहले ही वर्ष 2023-24 के दौरान 9 राज्यों को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹3649.40 करोड़ जारी करने की मंजूरी दे दी है। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए एसडीआरएफ के लिए ₹1,28,122.40 करोड़ आवंटित किए हैं। यह जानना भी जरूरी है कि प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पहले ही वर्ष 2023-24 के दौरान 27 राज्यों को एसडीआरएफ के केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹10,031.20 करोड़ जारी कर चुकी है। ■

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) के तहत 19 राज्य सरकारों को ₹6,194.40 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। साथ ही राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के तहत हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को ₹180.40 करोड़ जारी करने की मंजूरी दी है।

अग्निशमन सेवाएं और हुईं मजबूत

प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय द्वारा आपदाओं के दौरान न्यूनतम नुकसान की पहल की जा रही है

ब्यूरो

अग्निशमन सेवाओं को मजबूती दें, तो नुकसान का स्तर कम हो सकता है। यही सोच राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए आरंभ की गई योजना में देखी जा सकती है। प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय द्वारा भारत में आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली को मजबूत करके भारत को आपदा प्रतिरोधी बनाने और आपदाओं के दौरान 'शून्य मृत्यु' और संपत्ति का न्यूनतम नुकसान सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख पहल की जा रही हैं। इस बाबत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने 13 जून, 2023 को नई दिल्ली में हुई राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस योजना की घोषणा की थी।

इस योजना का उद्देश्य एनडीआरएफ के भीतर अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है, जिससे एनडीआरएफ की तैयारियों और क्षमता-निर्माण घटक के माध्यम से राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत किया जा सके। इस योजना में शामिल धन की बात करें, तो योजना के तहत परियोजनाओं/प्रस्तावों के लिए धन आवंटन के लिए, संबंधित राज्य सरकारों को इन परियोजनाओं/प्रस्तावों की कुल लागत का 25% (उत्तर-पूर्वी और हिमालयी (एनईएच) राज्यों को छोड़कर, जो 10% योगदान देंगे) अपने बजटीय संसाधन में से योगदान करना होगा। इस योजना का विवरण गृह मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रभाग की वेबसाइट https://ndmindia.mha.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इस योजना की शुरुआत के पीछे पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) की सिफारिश है, जिसके तहत, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) में से प्रत्येक (कुल राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एनडीआरएमएफ) और राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (एसडीआरएमएफ) का 10%) के 12.5 प्रतिशत के आवंटन की अनुमति तैयारी और क्षमता निर्माण की फंडिंग के लिए दी गई है। एनडीआरएफ के कुल कोष में से ₹5,000 करोड़ की राशि को 'अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण' के लिए प्राथमिकता से रखा गया है। बता दें कि निर्धारित आवंटन के विरुद्ध स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध देनदारियों का उनके पूरा होने की अवधि के बाद कोई स्पिल-ओवर नहीं होगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण निधि के तहत निर्धारित आवंटन से 'राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण' के लिए ₹5,000 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ योजना शुरू की है। कुल परिव्यय में से ₹500 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को उनके कानूनी और बुनियादी ढांचा-आधारित सुधारों के आधार पर प्रोत्साहित करने के लिए रखी गई है। इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और अग्निशमन सेवाओं के प्रमुख को पत्र भेजा गया है। ■

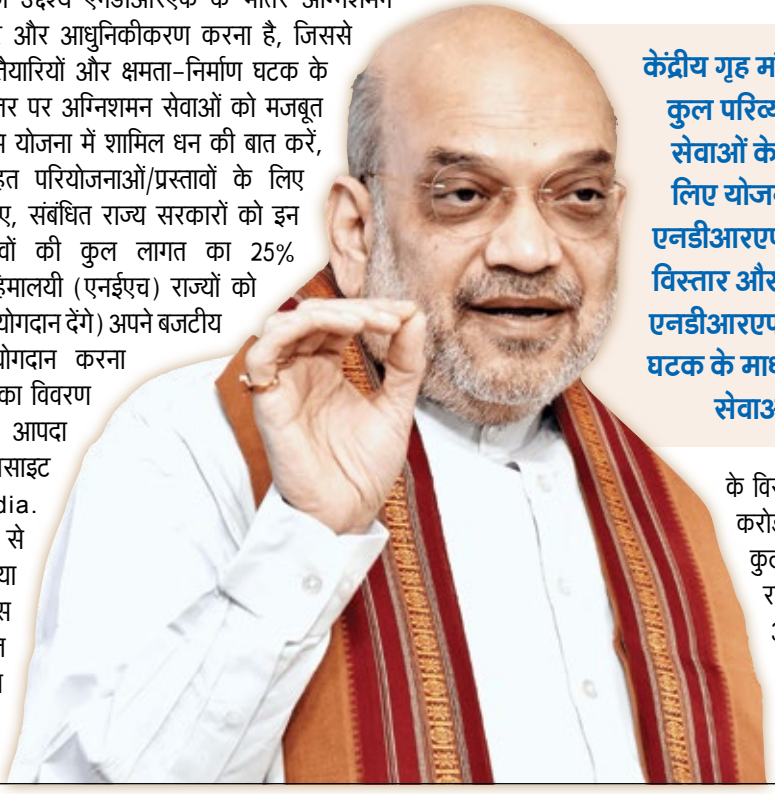

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ₹5,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए योजना शुरू की है। योजना का उद्देश्य एनडीआरएफ के भीतर अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण करना है, जिससे एनडीआरएफ की तैयारियों और क्षमता-निर्माण घटक के माध्यम से राज्य स्तर पर अग्निशमन सेवाओं को मजबूत किया जा सके।

हवाई अड्डों को मिला और अधिक सुरक्षा कवच

ब्यूरो

समय के साथ चुनौतियां भी नए-नए रूप में आ रही है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को पहले से अधिक आधुनिक और सामर्थ्यवान बना रहा है। वर्तमान चुनौतियों से निपटने के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की ओर से विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है। इसके चार प्रमुख घटक हैं- संचार एवं नियंत्रण केंद्र, घटना प्रबंधन केंद्र, विमानन अनुसंधान केंद्र और डेटा सेंटर। यह नियंत्रण केंद्र सुरक्षा बल के सुरक्षा प्रबंधों के अंतर्गत 66 हवाई अड्डों से संबंधित सभी धमकियों और सोशल मीडिया पर आने वाली अफवाहों पर नजर रखेगा। इसके साथ ही सातों दिन चौबीस घंटे डेटा पर नजर रखेगा और यात्रियों तथा यातायात के विश्लेषण की जानकारी देगा। यह केंद्र अति उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे कि डेटा केंद्र , अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला तथा आपात स्थिति में चुनौती से निपटने का काम करेगा।

परिचालन क्षमता में गुणात्मक विकास के लिए परिचालन अभ्यास, नई तकनीकी खोजों और मानव संसाधनों के विकास के साथ निरंतर गतिशील अनुकूलन की आवश्यकता होती है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का एयरपोर्ट सेक्टर मुख्यालय, केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की कार्यप्रणाली को पारंपरिक घटना आधारित सूचना संग्रह केंद्र से परिवर्तित कर उपयोगी विश्लेषणात्मक जानकारी इकट्ठी करने और वास्तविक समय में ही कार्रवाई करने की ओर अग्रसर है जिससे हवाई अड्डों की सुरक्षा के संचालन में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

इसके माध्यम से दिल्ली, मुंबई, बेंगलूरु, जम्मू, श्रीनगर और अमृतसर के साथ कई अन्य हवाई अड्डों पर अत्यंत व्यस्त और बेहद संवेदनशील स्थिति सहित जानकारी भी ली जाएगी। यह सुविधा यात्रियों की संख्या के बारे में वास्तविक जानकारी प्रदान करेगा, जो हवाई अड्डों की अधिकतम उपयोग के लिए संसाधन जुटाने में सहायक होगी। यह बम से संबंधित चुनौती, वी वी आई पी के आवागमन, अन्य प्रमुख घटनाओं, यात्रियों की जांच में लगने वाले समय

और पंक्ति प्रबंधन प्रणालियों पर नजर रखेगा।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह ने नई दिल्ली में महिपालपुर स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल परिसर के विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री शील वर्धन सिंह और बल के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह की ओर से कहा गया कि महिपालपुर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कैंप प्रगति के गौरव से गौरवान्वित है, क्योंकि आज अत्याधुनिक विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस, केंद्र आपात स्थिति के दौरान त्वरित निर्णय लेने में सहायता करते हुए खतरों की वास्तविक समय पर निगरानी करने में सक्षम होगा। एक परिष्कृत अनुसंधान केंद्र के साथ मिलकर, संस्थान विमानन सुरक्षा में सर्वोत्तम प्रथाओं के निर्माण को भी बढ़ावा देगा। ■

हवाई यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिबद्ध सरकार

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री, श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हवाई अड्डों की सुरक्षा और अधिक दुरूस्त करने के लिए के साथ समीक्षा बैठक की। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और आव्रजन अधिकारियों के साथ कुछ हवाई अड्डों पर क्षमता और जनशक्ति विस्तार की योजना की समीक्षा को लेकर बात हुई। कहा गया कि आगामी व्यस्ततम यात्रा सीजन में हवाई यात्रियों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बैठक का उद्देश्य देश में तेजी से बढ़ती घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मोबिलिटी से उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं पर विचार करना था। यात्रियों के लिए त्वरित, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए मानक विकसित और प्रदान करने के निर्देश दिए गए। गृह मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और अन्य एजेंसियों ने प्रमुख हवाई अड्डों पर सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विस्तार की दिशा में कई कदम उठाए हैं। ■

संवाद, सोच और सफलता

ब्यूरो

चार जुलाई को दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के सिनेटर श्री मोरे वॉट ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय से केंद्रीय गृह मंत्रालय में मुलाकात की। दोनों के बीच आपदा प्रबंधन को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। बैठक में विशेष रूप से आपदा प्रबंधन को लेकर चर्चा हुई और इसके संबंध में सूचनाओं के आदान प्रदान पर भारत-ऑस्ट्रेलिया ने अपनी साझा प्रतिबद्धता को दोहराया। मुलाकात को

हर व्यक्ति की सुरक्षा की सोच के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय काम करता आ रहा है। सभी मंत्री जनता के बीच जनता के हितों के लिए जनता से संवाद करते हैं। दूसरे देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान भी हर नागरिक की बात होती है।

लेकर स्वयं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री नित्यानंद राय का कहना है कि प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री की इस प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए नॉर्थ ब्लॉक में ऑस्ट्रेलिया के सिनेटर से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया के कृषि, मछली पालन तथा आपातकालीन प्रबंधन मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक में साझा हितों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।

- 13 और 14 जुलाई को साइबर सुरक्षा को लेकर जी20 की दो दिवसीय सम्मेलन की तैयारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कई दिनों से चल रही थी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री अजय मिश्रा समय-समय पर समीक्षा बैठक करते रहे। केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह के निर्देशन पर पूरी तैयारियों को लेकर वे विभागीय अधिकारियों से पूरी जानकारी लेते रहे। चार जुलाई को एक ऐसी ही बैठक की अध्यक्षता श्री अजय मिश्रा ने की। बैठक में गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) श्रीमती शिवगामी सुंदरी नंदा ने जानकारी साझा की।
- जी20 के दो दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान केंद्रीय गृह

राज्य मंत्री, श्री अजय मिश्रा ने भारत सरकार की साइबर सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्धता को दोहराया और कहा कि पहले सत्र में स्वयं केंद्रीय गृह मंत्री, श्री अमित शाह ने भी इस ओर ध्यान दिलाया है। उनका कहना है कि साइबर अपराधों की सीमा-रहित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, डिजिटल अपराधों का मुकाबला करने के लिए सभी देशों के कानूनों में कुछ एकरूपता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। रैंसमवेयर हमलों, महत्वपूर्ण व्यक्तिगत डेटा की बिक्री, ऑनलाइन उत्पीड़न और बाल शोषण से लेकर फर्जी समाचार और 'टूलकिट' के साथ गलत सूचना अभियान तक की घटनाएं साइबर अपराधियों द्वारा की जा रही हैं। इसलिए भारत ने जी20 के मंच से इस ओर पूरी दुनिया को एक साथ मिलकर इससे लड़ने का आह्वान किया है। विशेषज्ञों के सुझावों पर हर सरकार अमल करें, तो प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के साइबर सुरक्षित दुनिया की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। हिंसा को लेकर केंद्र सरकार हमेशा सतर्क रहती है और उसे रोकने के लिए लगातार काम कर रही है।

- हाल ही में पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हुए। जिस दौरान कई इलाकों में हिंसा की खबरें आईं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, श्री निशिथ प्रमाणिक ने हिंसा प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। 10 जुलाई को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सह कूचबिहार के सांसद, श्री निशिथ प्रमाणिक ने बंगाल के पंचायत चुनाव में बेलगाम हिंसा के घायलों और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। अस्पताल जाकर घायलों के इलाज के बारे में जानकारी ली और डॉक्टरों को निर्देश दिया कि सभी घायलों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले। ■

परियोजनाओं की समीक्षा से मिले सकारात्मक परिणाम

ब्यूरो

केंद्रीय गृह सचिव, श्री अजय कुमार भल्ला ने प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं की जम्मू-कश्मीर में समीक्षा की। ये सभी परियोजनाएं एनएचपीसी द्वारा सीधे तौर पर और जम्मू-कश्मीर सरकार के संयुक्त उद्यम के माध्यम से निष्पादित है। इस बैठक में सीएमडी एनएचपीसी और जम्मू-कश्मीर सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। हाल के महीनों के दौरान रैटले, किरू और क्वार जैसी परियोजनाओं में अच्छी प्रगति देखी गई है। अगले 3 वर्षों में जम्मू-कश्मीर में लगभग 3500 मेगावाट क्षमता जोड़ी जाएगी।

- 30 जून 2023 को केंद्रीय गृह सचिव, श्री अजय कुमार भल्ला ने वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों के साथ वामपंथी उग्रवाद को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के महानिदेशकों के साथ संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में गृह सचिव को वामपंथी उग्रवाद की स्थिति में सुधार, एसआरई जिलों की चल रही समीक्षा और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में विकासात्मक परियोजनाओं की स्थिति से अवगत कराया गया। गृह सचिव ने उठाए गए कदमों के लिए सुरक्षा बलों, राज्य प्राधिकरणों और अन्य संबंधित मंत्रालयों की सराहना की और सबसे अधिक प्रभावित जिलों को ध्यान में रखते हुए विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति में और तेजी लाने और संसाधनों की केंद्रित तैनाती सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

केंद्रीय गृह सचिव, श्री अजय कुमार भल्ला ने 26 जून से 10 जुलाई 2023 के बीच कई बैठकों की अध्यक्षता की। अलग-अलग मुद्दों पर आयोजित सभी बैठकों में आगामी कार्ययोजना को लेकर निर्देश और समीक्षा की गई। कई विदेशी प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को लेकर नई ताजगी दिखी।

- 3 जुलाई को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें सचिव आयुष के साथ केंद्रीय सशस्त्र बल के अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों और अधिकारियों को स्वास्थ्य को लेकर पहले से अधिक जागरूक करने और अपनी दिनचर्या में योग को शामिल करने के महत्व पर बात की गई। सीएपीएफ, असम राइफल्स और एनएसजी की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योग की बात की गई। योग के विशिष्ट प्रोटोकॉल तैयार करने और प्रशिक्षकों की एक कोर टीम को प्रशिक्षित करने के संबंध में चर्चा हुई। उच्च ऊंचाई सहित विभिन्न जलवायु परिस्थितियों, स्थलाकृतिक स्थानों, रेगिस्तान, उष्णकटिबंधीय और सामान्य स्थितियों पर तैनात सैनिकों के लिए योग को सुलभ कराया जाएगा। योग प्रोटोकॉल की प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने के लिए अनुसंधान प्रोटोकॉल विकसित करेगा और इन योग मॉड्यूल पर चिकित्सा अधिकारियों, मनोचिकित्सकों, नैदानिक मनोवैज्ञानिकों और शरीर विज्ञानियों का संवेदीकरण और प्रशिक्षण किया जाएगा।

भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त, श्री बैरी ओ'फैरेल एओ ने केंद्रीय गृह सचिव, श्री अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की। केंद्रीय गृह सचिव ने विदाई के अवसर पर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया।

- केंद्रीय गृह सचिव ने 6 जुलाई को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और अन्य हितधारकों के साथ बैठक की। इस बैठक में सूखे की स्थिति तैयार करने के लिए 12 सबसे अधिक सूखाग्रस्त राज्यों को उत्प्रेरक सहायता के लिए V-FC के राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) के तहत निर्धारित आवंटन से वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार किया गया। इस बैठक में राज्य सरकारों को अपने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करने के लिए एनडीएमए द्वारा तैयार किए गए टेम्पलेट को राज्य में प्रसारित करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की गई। भारत में ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त श्री बैरी ओ'फैरेल एओ ने केंद्रीय गृह सचिव से मुलाकात की। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त अपने कार्यकाल के अंत में भारत छोड़ रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्रालय की सक्रिय भागीदारी और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया साथ ही प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी व्यवस्था (एमएमपीए) को अंतिम रूप देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। ■

श्री अश्विनी वैष्णव*

प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण और साइबर सुरक्षा प्रत्येक के लिए आवश्यक

हमने सूचना क्रांति को करीब से देखा है। इस समय देश में 80 करोड़ से अधिक लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा है। ऐसे में सभी को साइबर सुरक्षा देना अति आवश्यक है। साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए सभी देशों का सहयोग जरूरी है। इसके लिए क्या—क्या समाधान हो सकते हैं इसको आपस में साझा करना होगा। सूचना क्रांति को देश के हर गांव तक पहुंचाना वर्तमान सरकार का लक्ष्य है। मैं खुद चाहता हूं कि देश के कोने-कोने में इंटरनेट की सुविधा पहुंचे। इसके लिए सरकार काम कर रही है और यह लक्ष्य जल्द ही पूरा होगा।

आए दिन सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति हो रही है। चुनौतियां भी आ रही हैं। यह चुनौतियां नई-नई तकनीक से साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं। भारत में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2015 में ह्यडिजिटल इंडियाह्ल मिशन लॉन्च किया गया इसके लिए सार्वजनिक-निजी सहभागिता (पीपीपी) मॉडल को अपनाया गया। डिजिटल इंडिया में निहित थी एक सहज भावना। वह थी प्रौद्योगिकी, आम नागरिक के जीवन के हर पहलू को छूए। यह जनता को सशक्त बनाने और डिजिटल विभाजन को पाटने का एक साधन होना चाहिए, जिसने कई विकासशील देशों में लंबे समय से प्रगति में बाधा उत्पन्न की है। भारत ने एक वैकल्पिक दृष्टिकोण अपनाया - सार्वजनिक-निजी भागीदारी का एक मॉडल जहां सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिकों ने व्यापक भलाई के लिए मिलकर काम किया। यहीं कारवां थमा नहीं। उसके बाद से इस बात का खास ध्यान रखा गया कि तकनीक और डिजिटल सुविधा पर कुछ बड़ी कंपनियों का या कुछ खास लोगों का ही अधिकार नहीं रहे, बल्कि समग्र रूप से समाज के उत्थान के लिए डिजिटल सुविधा एक शक्तिशाली उपकरण होना चाहिए। इसके लिए सहयोग बहुत जरूरी है। किसी अपराध को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से एक-दूसरे के साथ सभी देश सहयोग करते हैं, वैसा ही तालमेल साइबर सुरक्षा के लिए भी रखना होगा। नई-नई तकनीक से साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रतिदिन चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसलिए राष्ट्रीय, व्यक्तिगत और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हमें सहयोग भरा रवैया अपनाना ही होगा।

सरकार ने अपने फंड से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) प्रणाली को विकसित किया, जिससे सालाना दो ट्रिलियन डॉलर का ट्रांजेक्शन होता है और एक ट्रांजेक्शन को पूरा होने में सिर्फ दो सेकेंड का समय लगता है। ई-कामर्स से लेकर स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में सरकार यूपीआइ जैसे प्लेटफार्म विकसित कर रही हैं। ई-कॉमर्स के लिए समान प्लेटफॉर्म बनाए गए, जैसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) जिसमें 700 मिलियन से अधिक लोग शामिल थे, ओ एंड डी सी ने देश भर में उपभोक्ताओं और व्यवसायों को जोड़कर समावेशी विकास को बढ़ावा दिया। सरकार द्वारा विकसित को-विन प्लेटफॉर्म सार्वजनिक-निजी भागीदारी की ताकत का एक और प्रमाण था। इस मंच का लाभ उठाते हुए, लाखों कोविड-19 वैक्सीन खुराक को उल्लेखनीय दक्षता के साथ प्रशासित किया गया, जिससे अनगिनत लोगों की जान बचाई गई और वैश्विक संकट के दौरान आशा को बढ़ावा मिला। 1.4 बिलियन लोगों के लिए पूरी शेड्यूलिंग इतनी सफलतापूर्वक की गई कि 2 बिलियन से अधिक टीकों की खुराक बिना किसी दोष के सफलतापूर्वक दी गई।

डिजिटल सुविधा समान रूप से उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने इसका पूरा ध्यान रखा कि देश के हर कोने में इंटरनेट हो और लोग इसके इस्तेमाल करने में सक्षम हों। लगभग 84-85 मिलियन लोगों के पास पहले से ही इंटरनेट की पहुंच थी, हमने इस पहुंच का विस्तार करने की तत्काल आवश्यकता को पहचाना। भारत के प्रथम गाँव तक उच्च गुणवत्ता वाले ब्राडबैंड सेवा पहुंचे। इसके लिए भारतनेट कार्यक्रम के तहत 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध था कि भारत के हर घर में विश्वसनीय 4जी, 5जी और ब्रॉडबैंड कवरेज की पहुंच हो।

इस बार जी20 का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य है। हम प्रौद्योगिकी का लोकतंत्रीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, हम साइबर सुरक्षा की गहन चुनौती का भी सामना कर रहे हैं। साइबर खतरे जटिल एवं सीमाहीन हैं और लगातार विकसित हो रहे हैं, जिसके लिए त्वरित और सहयोगात्मक प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगमन ने साइबर सुरक्षा परिदृश्य में और जटिलताएं बढ़ा दीं है। ऐसे में इस विषय में एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अत्यावश्यक है।

साइबर सुरक्षा हेतु चुनौतियों को कम करने के लिए राष्ट्रीय, संगठनात्मक और व्यक्तिगत स्तरों पर मजबूत प्रयासों की जरूरत है। राष्ट्र को वैश्विक साइबर रक्षा नेटवर्क को बढ़ावा देकर, साइबर हमलों से निपटने के लिए समाधान विकसित करने और उन्हें लागू करने के लिए सहयोग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से ही अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधों से लड़ा जा सकता है। इसके लिए परस्पर सहयोग आवश्यक है।

राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (एनसीसीसी) और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति जैसी पहल देश के डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और साइबर खतरों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही हैं। इसके अलावा वैश्विक सहयोग की भावना को अपनाते हुए, भारत अपनी विशेषज्ञता और समाधान अन्य देशों के साथ साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ■

*(केंद्रीय रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री)

एक जुलाई को लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री, श्री अजय मिश्रा ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने संचारी रोगों को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास का संकल्प दोहराया और उपस्थित लोगों को इसकी शपथ दिलाई।

जम्मू-कश्मीर में पवित्र अमरनाथ यात्रा चल रही है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सभी यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा का ध्यान रख रही है। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक, डॉ एस.एल थाउसेन जम्मू-कश्मीर दौरे पर गए। उन्होंने तीर्थयात्रियों से भी बातचीत की और उनकी प्रतिक्रिया ली।

14वीं एनडीआरएफ टीम ने हिमाचल प्रदेश के मणिकरण घाटी में बचाव अभियान चलाया और 15 जुलाई तक 5070 लोगों को सुरक्षित निकाला। बेहद पेशेवर तरीके से एनडीआरएफ के 14वीं एनडीआरएफ के कमांडेंट श्री बलजिंदर सिंह इस अभियान की अगुवाई कर रहे हैं।

पुलिस अनसुंधान एवं विकास ब्यूरो के यूट्यूब चैनल 'पुलिस और सेवा' ने हाल ही में सुश्री तेजस्वी सतपुते, आईपीएस के नेतृत्व में सोलापुर पुलिस, महाराष्ट्र के 'ऑपरेशन परिवर्तन' पर विस्तृत प्रकाश डाला, जिसे 'लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार' से सम्मानित किया गया है।

भारत के वीर

देश के जवानों को श्रद्धांजलि और समर्थन

https://bharatkeveer.gov.in

दिशा-निर्देश

- आप सीधे भारत के वीर के खाते में (अधिकतम ₹15 लाख तक) दान कर सकते हैं या भारत के वीर कोष में दान कर सकते हैं।
- अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, प्रति वीर ₹15 लाख की सीमा तय की गई है और यदि राशि ₹15 लाख से अधिक है तो दाता को सतर्क किया जाएगा, ताकि वे या तो अपने योगदान को कम करने या योगदान के हिस्से को किसी अन्य भारत के वीर के खाते में डालने का विकल्प चुन सकें।
- भारत के वीर फंड का प्रबंधन प्रतिष्ठित व्यक्तियों और समान संख्या में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया जाएगा, जो आवश्यकता के आधार पर भारत के वीर परिवार को समान रूप से फंड वितरित करने का निर्णय लेंगे।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) के लिए फार्च्यूना पब्लिक रिलेशंस प्रा. लि. नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित व विबा प्रेस प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित

"डिजिटल प्रौद्योगिकी समानता स्थापित करने वाले एक तत्व के रूप में कार्य करती है और समावेशिता को बढ़ावा देती है। जी-20 के देश अपनी-अपनी क्षमताओं के साथ विशेष रूप से दक्षिणी दुनिया के देशों में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।"

-श्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

BPRD

आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो
गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्ग-48, महिपालपुर,
नई दिल्ली-110037